जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 117 प्रभात बीकानेर, गुरूवार, 20 नवम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

बिहार के झटके के बाद इंडिया गठबंधन में बेचैनी सी है राहुल गांधी के विपक्ष के नेता पद के बारे में

कांग्रेस ने संसद के आगामी सत्र से पहले विपक्ष की बैठक बुलाने का प्रयास किया था वोट चोरी के मुद्दे पर, पर यह प्रयास विफल हुआ

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 नवम्बर। बिहार में मिली करारी हार ने इंडिया ब्लॉक के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि राज्य-आधारित दल अब राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेता मानने में असहज दिखाई दे रहे हैं।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटों तक सीमित रखने के बाद, विपक्ष, खासकर कांग्रेस, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हार के बाद, अपना "मोमैन्टम" (अपनी गति) बनाए नहीं रख सका। झारखंड में कुछ मजबूती दिखी, जहाँ इंडिया ब्लॉक ने विधानसभा की 81 में से 56 सीटें जीतीं। जम्मू-कश्मीर में भी विपक्षी गठबंधन ने 90 में से 49 सीटें जीतीं। लेकिन बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद माना जा रहा है कि भाजपा ने 2024 की हार की भरपाई कर ली है।

इंडिया ब्लॉक के भीतर बेचैनी साफ दिख रही है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाकर "वोट चोरी" मुद्दे को संसद में उठाने की कोशिश की। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित, गठबंधन के प्रमुख पार्टनरों ने इस पहल में खास रुचि नहीं दिखाई है।

- प्रमुख विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस व सपा ने इस प्रयास से दूरी बनाने का मन बनाया।
- महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी), जो कांग्रेस नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कांग्रेस के साथ पार्टनर थी, ने भी कांग्रेस का मखौल उड़ाया कि कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद पाकर इतरा तो रही है, पर, उसका जमीनी प्रदर्शन काफी लड़खड़ा रहा है।
- आगामी असैंबली चुनाव में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं देंगे, ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के चुनावों में ज्यादा एकॉमोडेट करने के मूड में नहीं है।
- तमिलनाडु में द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन में भी अब उतनी गर्मी नहीं है।
- द्रमुक, कांग्रेस से अप्रसन्न है, क्योंकि कांग्रेस सिनेस्टार व राजनीतिज्ञ विजय से नज़दीकी दिखाती रही है। अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे गठबंधन से नाता तोड़ रहे हैं तथा अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना ही सार्थक समझ रहे हैं।

महाराष्ट्र की घटनाएँ बहुत कुछ सीख देती नजर आ रही हैं। बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने की कांग्रेस की घोषणा के बाद, शिवसेना (यूबीटी), जो पहले महा विकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा थी, ने कांग्रेस का मज़ाक उड़ाया। पार्टी के मुखपत्र "सामना" के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपनी "राष्ट्रीय पार्टी" की पहचान का ढोल पीटकर अपना महत्व साबित करना चाहती है, जबकि उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर होता जा रहा है।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का साथ मिलना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में, जहाँ चुनाव अगले साल की शुरुआत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महिला सब इन्सपैक्टर सवा लाख रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 19 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय की जयपुर नगर तृतीय टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के गांधीनगर थाने की महिला पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) राजकुमारी जुनेजा को सवा लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी जयपुर नगर तृतीय टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि पुलिस थाना

- गांधी नगर पुलिस थाने में तैनात राजकुमारी जुनेजा को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा।

गांधीनगर में दर्ज प्रकरण में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने एवं मुकदमे में एफआर लगाने की एवज में महिला पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) राजकुमारी जुनेजा दो लाख रुपये की रिश्वत मांग रही है।

इस पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय टीम के पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) राजकुमारी जुनेजा को सवा लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

नीतीश ने अपने निकटस्थ विश्वासी को नये मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया

चौंकाने वाले इस निर्णय से नीतीश कुमार ने साफ मैसेज दिये, राजनीतिक नज़दीकी नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त छवि दिलायेगी राजनीतिक पद नई सरकार में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 नवम्बर। बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने नए कार्यकाल की तैयारी करते हुए एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है, अब राजनीतिक नज़दीकी किसी को जवाबदेही से नहीं बचा पाएगी। एक चौंकाने वाले कदम के अन्तर्गत, नीतीश ने अपने पुराने भरोसेमंद साथी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी को अपनी कैबिनेट से बाहर कर दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में गहन चर्चाएँ शुरू हो गईं और सहयोगी भाजपा भी सतर्क हो गई है।

इस फैसले को व्यापक रूप से साफ-सुथरे शासन की छवि मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय, जब भाजपा के उपमुख्यमंत्री पद के दावेदार पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के कई आरोप लगे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि नीतीश का यह कदम न केवल अपनी पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश है, बल्कि भाजपा पर भी अपने निर्णयों की

- प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, दस्तावेज व सबूत पेश करते हुए लगाये थे।
- नीतीश के निर्णय से भाजपा भी दबाव में आ गई है, क्योंकि भाजपा के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के कई संगीन आरोप हैं।
- अतः भाजपा भी अपनी तरफ से प्रस्तावित मंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट को भी पुनः गहराई से चैक करने को मजबूर हो गई है।

समीक्षा करने तथा अपने पसंदीदा नेताओं को खँगालने का अप्रत्यक्ष दबाव है।

अशोक चौधरी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से कुछ ही सप्ताह पहले, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों, जिनमें चौधरी भी शामिल थे, पर गंभीर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुये, कुछ दस्तावेज़ जारी किए थे। प्रशान्त किशोर द्वारा किये गये इन खुलासों से जेडीयू के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई थी और मुख्यमंत्री को राजनीतिक रूप से कठिन परिस्थिति में डाल दिया था।

अशोक चौधरी करोड़ों रुपये की जमीन सौदेबाजी में कथित संलिप्तता को लेकर जांच के दायरे में हैं। इस प्रकरण से सरकारी प्रभाव के दुरुपयोग पर सवाल खड़े हो गये थे। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया था और नीतीश कुमार पर "दागी मंत्रियों को चुपचाप बचाने" और साफ-सुथरे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की

संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस बैठक में सक्रिय भूमिका निभाई अपनी उपस्थिति से

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 नवम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि भाजपा "वोट चोरी" के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एस.आई.आर.) प्रक्रिया का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर केवल "प्रशासनिक विफलता" नहीं, बल्कि "मौन की मिलीभगत" का आरोप लगाया।

यह बयान उन्होंने यहां आयोजित एक व्यापक रणनीति समीक्षा बैठक के बाद जारी किया। इस बैठक में एआईसीसी के महासचिव, प्रभारी, पीसीसी प्रमुख, सीएलपी नेता और उन 12 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के एआईसीसी सचिव शामिल थे, जहाँ एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

- बैठक में एआईसीसी के महासचिव, प्रदेशों में नियुक्त प्रभारी, पीसीसी के पदाधिकारी व कांग्रेस विधायक दल के वरिष्ठ सदस्य भी बुलाए गए थे, विशेषकर उन बारह राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों से जहाँ एसआईआर प्रक्रिया चालू है।
- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद पुनः दोहराया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया का वोट चोरी साजिश में उपयोग कर रही है तथा चुनाव आयोग चुप्पी साध कर इसमें मूक समर्थन दे रहा है। यह कोई प्रशासनिक फेलियर का मुद्दा नहीं है।

खड़गे ने कहा कि जब जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा पहले से ही कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है।

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं, बीएलओ और जिला, शहर तथा ब्लॉक अध्यक्षों से लगातार सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि "हम ऐसी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान वि.वि. में कुलपति की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 19 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा को नियुक्ति देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रोफेसर अल्पना कटेजा को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की

- प्रो. अल्पना कटेजा पर आरोप है कि आवंटन करते समय उन्होंने लंबित अपराधिक प्रकरण को छुपाया।

एकलपीठ ने ये आदेश प्रोफेसर महिपाल सिहाग की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में दायर स्टे एप्लिकेशन पर आदेश जारी करने से पहले प्रोफेसर अल्पना को सुनवाई का मौका दिया जाना उचित रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रवासी राजस्थानी विभाग बनेगा, ग्लोबल केपबिलिटी सैंटर स्थापित होंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए

जयपुर, 19 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, राजस्थान ग्लोबल केपबिलिटी सेंटर पॉलिसी के अनुमोदन तथा आरवीयूएनएल व सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आज मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग' के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

- प्रवासी राजस्थान विभाग से विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान स्थापित होगा व लोकप्रिय बनेगा।
- ग्लोबल केपबिलिटी सैंटर नीति के तहत 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनसे 1.50 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन्स के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा।

कर्नल राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल केपबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का अनुमोदन किया है। यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच जॉइंट वेंचर(जे.वी.) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह जेवी खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी।

एकल पट्टा क्लोज़र रिपोर्ट वापस लेने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी

जयपुर, 19 नवंबर। प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा मामले में एसीबी ने बुधवार को एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट में कहा कि वह 19 जुलाई 2022 की क्लोजर रिपोर्ट को वापस लेना चाहती है, ताकि मामले में आगामी जांच

- एसीबी ने विशेष कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में आगामी जाँच करने के लिए कहा है। अतः क्लोज़र रिपोर्ट वापस लेने की अनुमति दें

की जा सके। एसीबी की ओर से केस ऑफिसर व एडिश्नल एसपी महावीर प्रसाद कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2022 की क्लोजर रिपोर्ट में खामियां रह गई थीं और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोलह जजों, एक सौ तेइस रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी, चौदह राजदूत व सेना के एक सौ तैंतीस रिटायर्ड अफसरों ने एक खुली चिट्ठी लिखी

इस पत्र में उन्होंने राहुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव आयोग को जानबूझ कर कमज़ोर व बदनाम करने की कोशिश की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 नवंबर। एक सोची-समझी और संगठित प्रतीत हो रही कोशिश के तौर पर, सिविल सोसायटी के 272 वरिष्ठ सदस्यों ने एक खुले पत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर भारतीय चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) पर "वोट चोरी" जैसे बेबुनियाद और भड़काऊ आरोप लगाकर उसकी साख कमजोर करने का आरोप लगाया है। इन वरिष्ठ सिविल सोसायटी सदस्यों में 16 जज, 14 राजदूतों, सहित 123 पूर्व नौकरशाह तथा 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं।

इस बयान का समर्थन करने वालों में कई प्रमुख नाम भी शामिल हैं, जैसे पूर्व रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व जम्मू-

- पत्र के अनुसार, राहुल गांधी ने कई बार पुरजोर ढंग से यह कहा है कि उनके पास वोट चोरी के अकाट्य सबूत हैं, जिनको अगर उन्होंने पेश किया तो ऐसा बम फटेगा कि चुनाव आयोग को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।
- पत्र के अनुसार, इन नाटकीय आरोपों के बावजूद आजतक भी राहुल गांधी या कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है, केवल सेवारत व रिटायर्ड चुनाव आयुक्तों को धमकियाँ दी हैं कि वे बख्शे नहीं जाएंगे।
- आरोपों के जवाब में कांग्रेस का कहना है कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोग भाजपा के चिंतन व विचारों से सहानुभूति रखने वाले लोगे हैं, जिनके आरएसएस व मोदी सरकार से गहरे संबंध रहे हैं, जैसे रिटायर्ड राजनयिक अधिकारी लक्ष्मी पुरी, जिन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, पैट्रोल मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी हैं।
- कांग्रेस का प्रत्युत्तर में कहना है कि, इस सार्वजनिक खुली चिट्ठी का एक ही मकसद है कि मोदी सरकार का विरोध करने वाले लोगों की विवसनीयता खत्म हो जनता के मन में।

कश्मीर डीजीपी एस. पी. वैद, पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी और लंबे सार्वजनिक सेवा करियर में रहे अन्य प्रमुख लोग।

इन लोगों की यह प्रतिक्रिया उस समय आई है, जब पिछले कई दिनों से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और एस.आई.आर. (सिस्टमैटिक इंटरनल रिवीजन) प्रक्रिया पर आरोपों की बौछार कर रखी है और दावा किया है कि आयोग ने वोट चोरी को संभव बनाया।

कांग्रेस बार-बार कहती रही है कि आयोग की कार्रवाई "बेहद निराशाजनक" रही है और इस बात का सबूत भी मांगा है कि आयोग राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है।

"असॉल्ट ऑन नेशनल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए द.अफ्रिका जायेंगे

नयी दिल्ली 19 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी-20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका की तीन दिन की यात्रा पर जाएंगे ।

यह ग्लोबल साउथ में 22-23 नवंबर को आयोजित होने वाला लगातार चौथा जी- 20 शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमन्त्री -20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी तीन सत्रों में संबोधन की उम्मीद है। जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री द्वारा जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे।

- तीन दिन की यात्रा पर वे शुक्रवार को रवाना होंगे।